ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

14 मार्च, 2018 • वर्ष 1, अंक 8

सात दिन – सात पृष्ठ

वाराणसी में आगमन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

- वाराणसी को मिली विकास योजनाओं की सौगातें
- विंध्य धाम में यूपी को मिला सबसे बड़ा सोलर प्लांट
- न्याय व्यवस्था का सशक्तीकरण
- महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण
- ई–नेम योजना में यूपी बना देश में अग्रणी
- गांवों में इलाज के लिए 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

गंगा के तट पर कला और संस्कृति के मध्य भारत और फ्रांस के आपसी संबंधों को नया आयाम

गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व के प्राचीनतम व जीवन्त शहरों में सम्मिलित काशी में भारत और फ्रांस के मध्य प्रगाढ़ होते मित्रता के संबंधों की नई इबारत लिखी गई, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों द्वारा दोनों देशों के मध्य संबंधों को वैश्विक मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ वाराणसी भ्रमण के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को नई ऊचाईयां तथा ऊर्जा प्रदान की। वाराणसी से मीरजापुर तक प्रतिक्षण विकास की रूपरेखा रचते हुए तथा गंगाजल को साक्षी बनाकर वर्ल्ड क्लास टूरिज्म की नयी इबारत लिखी गई।

शहर तक गांव तक हर क्षेत्र को विकास की सौगात

प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे में वाराणसी के शहरी तथा ग्रामीण सभी क्षेत्रों को लगभग आठ सौ करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने वाराणसी में पूर्ण हो चुकी कई परियोजनाओं को जनता को समर्पित करते हुए कई नवीन परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनके पूरा होने के उपरान्त इस नगरी की एक अलग ही पहचान होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा काशीवासियों द्वारा किए गए अविमरणीय स्वागत से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों अभिभूत हो गये।

भारत में 'अतिथि देवो भव:' की प्रचीन परम्परा है और फ्रांस के राष्ट्रपति के वाराणसी भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा वाराणसी की जनता ने बनारसी परम्परा का कुशलता से निर्वहन किया। काशी दर्शन के लिये आये विदेशी मेहमान तथा स्वयं प्रधानमंत्री जी भी इस अभूतपूर्व स्वागत से भावविभोर हो गये और वाराणसी भारत और फ्रांस के प्रगाढ़ होते संबंधों का साक्षी बना।

'आयुष्मान भव' से 50 करोड़ निर्धनों की होगी चिकित्सा

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि 'आयुष्मान भव' योजना के माध्यम से निर्धनों को पांच लाख रूपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जायेगी। बीमा कम्पनियों की मदद से इस योजना के द्वारा लगभग 10 करोड़ निर्धन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रकार लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे।

इस योजना से निर्धन व्यक्ति भी पाँच लाख रूपये तक का चिकित्सा सुविधा का लाभ नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

योजना के अन्तर्गत अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर भी कार्य किया जायेगा, जिससे रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे।

वाराणसी में प्रधानमंत्री ने मंडुवाडीह स्टेशन से मंडुवाडीह-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा रेल मंत्री मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। इस ट्रेन से उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य आवागमन में यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और उनको कम समय में आरामदेह यात्रा का अनुभव मिलेगा।

मुख्यमंत्री जी की सराहना

प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक्शन मोड में चल रही है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अत्यन्त तीव्र गति से विकास कार्य कराये जा रहे हैं, जिससे जल्द ही लोगों को बदलाव महसूस होगा।

600 करोड़ से होगा वाराणसी में सीवरेज ट्रीटमेंट

वाराणसी को विद्युत तारों के झुंड से मुक्ति दिलायी गई है। रेलवे सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सड़क मार्ग में सुधार के लिए कई योजनाएं चल रही हैं।

सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 600 करोड़ रुपए की योजना पर काम चल रहा है। यहां की सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण सम्भव हुआ है।

वाराणसी को मिली सौगातें

- महमूरगंज–मण्डुआडीह मार्ग पर रेलवे सम्पार सं. 3ए रेल उपरिगामी सेतु
- पुलिस लाइन वाराणसी में एस.टी.एफ. का अनावासीय भवन
- सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय डिग्री कालेज, जक्खिनी, वाराणसी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2 कक्षायें तथा लैब
- लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर, वाराणसी का उच्चीकरण
- नव सृजित तहसील राजा तालाब का निर्माण कार्य
- गंगा दर्शन गेस्ट हाउस
- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, कल्लीपुर ग्राम पेयजल योजना

इन योजनाओं से बदलेगी काशी की तस्वीर

- लहरतारा से फुलवरिया जे.पी. मेहता इण्टर कालेज–सेन्ट्रल जेल मार्ग पर शिवपुर चुंगी पर सम्पार संख्या 4 पर बनेगा 4–लेन आर.ओ.बी.
- लहरतारा से फुलवरिया जे.पी. मेहता इण्टर कालेज–सेन्ट्रल जेलमार्ग पर शिवपुर चुंगी पर सम्पार संख्या 5–सी पर बनेगा आर.ओ.बी.
- लहरतारा से फुलवरिया जे.पी. मेहता इण्टर कालेज–सेन्ट्रल जेल मार्ग पर शिवपुर चुंगी पर वरुणा नदी पर सेतु का होगा निर्माण
- वरुणा नदी पर कोनिया–सलारपुर मार्ग पर कोनिया घाट के सामने होगा सेतु का निर्माण
- पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी–औड़िहार सेक्सन किमी 197/3–4 के अन्तर्गत वाराणसी–गाजीपुर मार्ग सम्पार संख्या 20 स्पेशल पर बनेगा 03–लेन रेल उपरिगामी सेतु
- शिवपुर–लहरतारा–फुलवरिया मार्ग पर होगा 4–लेन का निर्माण
- बेला–पहड़िया को एकल लेन से दो लेन तक होगा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
- सारनाथ से मुनारी होते हुए रौना खुर्द तक होगा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य
- धरसौना से नियार होते हुए रजला गोमती नदी के किनारे तक होगा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य
- राजातालाब पुलिस चौकी से कौशलपुर होते हुए जक्खिनी तक होगा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य

560 करोड़ रूपये है प्लांट की लागत

मीरजापुर के दादरकलां ग्राम में स्थित 75 मेगावाट का यह सोलर प्लांट यूपी का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। फ्रांस के सहयोग से तैयार इस प्लांट की लागत लगभग 560 करोड़ रूपये आई है। इस प्लांट के माध्यम से केवल मीरजापुर ही नहीं, वरन् इलाहाबाद को भी भरपूर बिजली मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

विंध्य धाम में यूपी को मिला सबसे बड़ा सोलर प्लांट

विंध्यवासिनी धाम मातृ ऊर्जा के प्रमुख आध्यात्मिक स्रोत के रूप में विश्व विख्यात है। इसी क्षेत्र को आधुनिक युग के शक्ति उत्पादन केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में मीरजापुर में छानबे ब्लॉक के दादरकला गांव में 75 मेगावाट के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया।

सौर ऊर्जा के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है तथा लागत में भी कमी आती है। इसीलिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु निर्मित यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। विंध्यांचल की मनारेम पहाड़ियों के मध्य स्थित मीरजापुर जिले के दादरकला में यूपीनेडा द्वारा लगभग 155 हेक्टेयर भू–भाग पर सोलर प्लाण्ट में 318,120 पी.वी. पैनल्स लगाए गए हैं। इस संयंत्र का निर्माण एक फ्रांसीसी कम्पनी द्वारा किया गया है।

1.5 लाख
घरों को रोशन करेगी प्लांट से उत्पादित बिजली

15.6 करोड़
यूनिट बिजली हर साल उत्पादन करेगा प्लांट

इस प्लांट में सूर्योदय के साथ ही ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो जायेगा, जो सूर्यास्त तक जारी रहेगा। प्रदेश के इस सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के द्वारा प्रति माह लगभग एक करोड़ 30 लाख यूनिट तथा प्रति वर्ष लगभग 15.6 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है।

इस प्लांट के माध्यम से उत्पादित बिजली मिर्जापुर के जिगना स्थित यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत उपकेन्द्र को दी जायेगी और शेष बिजली इलाहाबाद को दी जायेगी।

इस प्लांट के माध्यम से सौर ऊर्जा के भरपूर दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा और मीरजापुर के दलित व आदिवासी बहुल अत्यन्त पिछड़े इलाकों तक भी रोशनी पहुंच सकेगी। ■

न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु कृतसंकल्प है राज्य सरकार

न्यायपालिका लोकतंत्र का अत्यन्त सशक्त स्तम्भ है। प्रजातंत्र की सफलता स्वतंत्र एवं सुदृढ़ न्यायपालिका पर निर्भर है। रूल ऑफ ला सभ्य समाज की आत्मा है। कानून से ही विकास और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 41वें अधिवेशन में अपने उद्बोधन में कहा कि आमजन को त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार न्यायपालिका को हर सम्भव सहयोग उपलब्ध करायेगी।

लम्बित वादों की संख्या हो कम

योगी जी ने न्यायिक अधिकारियों से न्यायालयों में लम्बित वादों की भारी संख्या को कम करने के लिए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की न्यायिक कार्य में आधे घण्टे की वृद्धि का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लिए न्यायिक अधिकारियों को अपनी ओर से सार्थक पहल करनी चाहिए। महापुरूषों की जयन्ती पर होने वाली 15 छुट्टियों को समाप्त करने से प्रदेश की जी.डी.पी. में हुई 50 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्य की अवधि में वृद्धि का प्रभाव बहुत उपयोगी हो सकता है।

> न्याय का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गरीबों, वंचितों और महिलाओं के प्रकरण में विशेष रूप से शीघ्रता एवं तत्परता की आवश्यकता है। पुराने मुकदमों के साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बच्चों, वृद्धों एवं विचाराधीन बन्दियों के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण होना चाहिए।
>
> **–योगी आदित्यनाथ**

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों तथा जनोपयोगी सेवाओं हेतु 24 नयी स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। इलाहाबाद में 395 करोड़ रुपए की लागत से न्याय ग्राम टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए नये वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में न्यायालय भवनों व न्यायिक अधिकारियों के आवास के नवनिर्माण व उनकी मरम्मत हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था करायी गयी है।

परिवार और समाज में शांति, राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। इसके दृष्टिगत 111 अतिरिक्त परिवार न्यायालय गठित किए गए हैं। भू-अर्जन के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद न्यायाधीश स्तर के 13 भू-अर्जन न्यायालयों का गठन भी किया जा चुका है। प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में कॉमर्शियल न्यायालयों के गठन के निर्णय के तहत 13 कॉमर्शियल न्यायालयों का गठन भी कर लिया गया है।

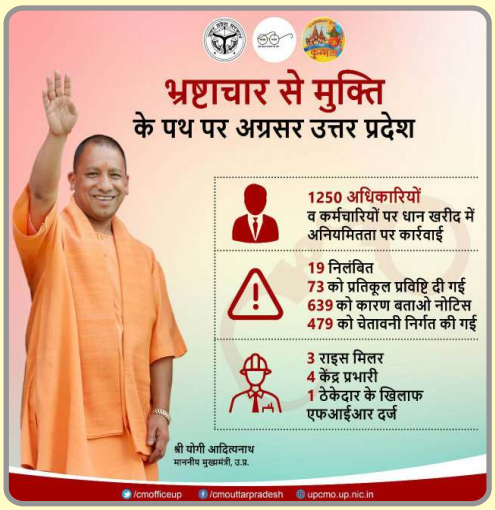

3.2 करोड़
नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन मिले उज्ज्वला योजना में

7.88 करोड़
महिला उद्यमियों को लोन दिए गए मुद्रा योजना में

1.26 करोड़
बैंक खाते खोले गये सुकन्या समृद्धि योजना में

16.42 करोड़
महिलाओं के बैंक खाते खुले प्रधानमंत्री जन–धन योजना में

महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कार्य कर रही है सरकार

वर्तमान समय में नारी शक्ति ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए देश और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नये भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं को सशक्त, सबल और देश के समग्र विकास में बराबर का भागीदार बनाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ–साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है।

महिलाओं के हित में सचालित हैं कई योजनाएं

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा **बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ** अभियान चलाया जा रहा है। बेटियों को सशक्त करने के लिए **सुकन्या समृद्धि योजना**, गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाकर मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु **उज्ज्वला योजना**, महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु **प्रधानमंत्री जन धन योजना**, महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए **मुद्रा लोन** तथा **स्टैंड अप इंडिया** संचालित की जा रही हैं।

महिला हेल्पलाइन से महिलाओं को तत्काल सहायता

महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ आदि घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा **एण्टी रोमियो स्क्वाड** के गठन जैसे कई प्रभावी कदम उठाये गये हैं। कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका इससे सहायता प्राप्त कर सकती है। प्रदेश में सभी जनपदों में **'181' महिला हेल्पलाइन एवं रेस्क्यू वैन** का संचालन हो रहा है।

महिलाओं के लिए विशेष बजट की व्यवस्था

राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 के बजट में महिला एवं बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग 8 हजार 815 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना सबला हेतु लगभग 351 करोड़ रुपये, समन्वित बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार हेतु 3 हजार 780 करोड़ रुपये, शबरी संकल्प योजना हेतु 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण अनुदान हेतु 1 हजार 263 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है।

शिक्षित समाज ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। इसलिए बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्पित है। ग्रेजुएशन स्तर तक की सभी बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा दिलाने के लिए 'अहिल्याबाई नि:शुल्क शिक्षा योजना' संचालित की जा रही है। वर्ष 2018–19 के बजट में राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

–योगी आदित्यनाथ

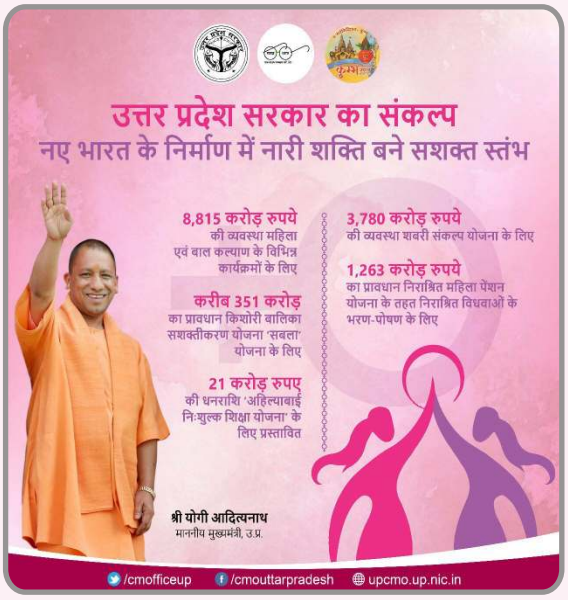

एग्री जंक्शन से कृषि क्षेत्र में मिलेगा रोजगार

प्रदेश में 1000 एग्री जंक्शन के माध्यम से युवाओं को स्वावलम्बी बनायेगी सरकार

प्रदेश सरकार कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने तथा इस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सार्थक सहभागिता हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार कृषि स्नातकों तथा परास्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश में एक हजार 'एग्री जंक्शन' स्थापित करेगी।

एग्री जंक्शनों के माध्यम से किसानों को बीज, खाद और कीटनाशकों के लिए ब्लाक अथवा अपने गांव से दूर नहीं जाना पड़ेगा, यह सारी सुविधाएं उन्हें अपने गांव में ही मिल सकेगी।

एग्री जंक्शन के लिए सरकार लाभार्थी को दुकान के लिए एक वर्ष के किराये के तौर पर दस हजार रूपये तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एग्री जंक्शन पर अच्छे और उन्नतशील बीजों के अतिरिक्त खेती से जुड़ी अन्य कई सुविधाएं भी मिलेंगी।

एग्री जंक्शनों के माध्यम से युवाओं में निश्चित तौर पर कृषि को कॉरियर के तौर पर अपनाने की इच्छा जागृत होगी। प्रदेश में एक हजार एग्री जंक्शन की स्थापना से न केवल युवाओं को स्वावलम्बी बनाया जा सकेगा, वरन् किसानों के जीवन स्तर में सुधार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महान संकल्प को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

ई-नेम योजना में यूपी बना देश में अग्रणी

प्रदेश की 100 मण्डियाँ ई-नेम पोर्टल से जुड़ीं

राष्ट्रीय कृषि बाजार में कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 100 मण्डियों को ई-नेम पोर्टल से सम्बद्ध कर लिया गया है। ई-नेम योजना में उत्तर प्रदेश से देश के सर्वाधिक 26 लाख किसान तथा 32 हजार व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं।

किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए हेल्प लाइन नम्बर-155241 भी स्थापित है। किसान विभिन्न मण्डियों के फसलों और कृषि उत्पादों के नवीनतम मूल्यों की जानकारी और खेती से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्पलाइन का उपयोग कर रहे हैं।

एम-पासबुक से घर बैठे देखें खाते का विवरण

प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के विकास के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। किसान अपने खाते से सम्बन्धित विवरण अपने मोबाइल पर ही देख सकें और उन्हें बैंक तक जाने की भी आवश्यकता न पड़े, इसलिए मोबाइल ऐप **एम-पासबुक** शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से खातों का विवरण मोबाइल पर भी देखा जा सकता है तथा उसका प्रिन्ट भी प्राप्त किया जा सकता है। इस ऐप में सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए बैंक के सभी खातों के लेन-देन का विवरण मात्र एक क्लिक पर प्राप्त किया जा सकता है।

कृषि अपशिष्ट से किसानों को होगी अतिरिक्त आमदनी

कृषि अपशिष्ट को पर्यावरण के प्रदूषण का प्रमुख कारक माना जाता है और अब तक इसके निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। परन्तु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कृषि अपशिष्ट के समुचित निस्तारण हेतु गंभीर हैं।

सरकार कृषि अपशिष्ट से बायो गैस बनाने के संयंत्र लगाने हेतु प्रयासरत है, जिससे कृषि अपशिष्ट का उचित निस्तारण होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही इससे होने वाली अतिरिक्त आय से किसान भी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

10 हजार रोजगार के अवसर

वर्तमान में गढ़ मुक्तेश्वर की आबादी लगभग 55 हजार है। यहाँ 5000 करोड़ रूपये के निवेश के फलस्वरूप जो भी विकास कार्य होंगे, उनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार यहाँ के स्थानीय निवासियों हेतु रोजगार के भरपूर अवसरों का सृजन होगा। प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा गढ़मुक्तेश्वर के विकास के लिए एक कंसल्टेंट भी नियुक्त कर दिया गया है। कंसल्टेंट द्वारा विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त सरकार द्वारा कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा।

गढ़मुक्तेश्वर बनेगा वर्ल्ड क्लास आध्यात्मिक सिटी

गढ़मुक्तेश्वर महाभारत काल से ही अपनी आध्यात्कि पहचान हेतु विख्यात है। इसी पहचान को अक्षुण्ण रखने हेतु इसे वर्ल्ड क्लास आध्यात्मिक सिटी के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रयत्नशील हैं। मलेशिया की एक कंपनी ने गढ़मुक्तेश्वर तथा उसके निकटवर्ती गंगा नदी के किनारे स्थित इलाकों को कायाकल्प करने हेतु 5000 करोड़ रूपये का एमओयू साइन किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट में गढ़मुक्तेश्वर के विकास के लिए 20 करोड़ रूपये की प्रथम किश्त प्रस्तावित की है। योजना के अतंर्गत गढ़मुक्तेश्वर के धार्मिक स्थलों, आध्यात्मिक केन्द्रों सहित प्रमुख स्थलों का जीर्णोद्धार तथा विकास किया जायेगा। तीर्थ यात्रियों के ठहरने हेतु उच्चस्तरीय सुविधायुक्त होटल तथा धर्मशलाओं का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परिवहन के साधन, चिकित्सा सुविधाएं, पार्क, शौचालय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक आयोजनों के लिए स्थलों का विकास भी होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्निशमन की व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये 25 करोड़ 39 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 12 करोड़ 69 लाख 51 हजार रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी हैं।

गांवों में इलाज के लिए मिलेंगी 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट

दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को समय पर समुचित इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए कई निवेशकों ने रूचि प्रकट की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इन मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन पीपीपी मोड पर किया जायेगा। इस योजना हेतु विशेष तौर पर जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) तथा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिण्ड्रोम (एईएस) प्रभावित जनपदों गोरखपुर तथा बस्ती में संचालित किया जायेगा, जिससे इन बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिल सके। कुल 36 जनपदों में इन यूनिटों का संचालन प्रस्तावित है। सभी जनपदों में कुल मिलाकर 170 मेडिकल मोबाइल यूनिट संचालित की जाएंगी। इन मोबाइल यूनिट के भीतर ही मरीज की स्थिति के अनुसार बैठाकर अथवा लिटाकर जांच करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी